मुख्य बिन्दु

बजट 2022–23

छत्तीसगढ़ शासन

बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी की नवीन घोषणाएं

➢ **राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना**

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3 लाख 54 हजार 513 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 08 लाख की प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है।
- आगामी वर्ष से भूमिहीन कृषि मजदूरों की वार्षिक सहायता राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 7 हजार किया जायेगा।
- आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी आदि जिनमें आदिवासियों के देवस्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया भी शामिल है, को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ दिया जायेगा।

➢ ग्राम पंचायतों को और अधिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की कड़ी में अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन पचांयतों द्वारा किया जायेगा। साथ ही, किसी भी ग्राम पंचायत की सहमति के बिना पंचायत क्षेत्र में कोई भी खदान संचालित नहीं की जायेगी।

➢ **नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जायेगी।**

➢ **जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि**

- जनपद पंचायत अध्यक्ष – 6000 रूपये से बढ़कार 10000 रूपये मासिक
- जनपद पचायत उपाध्यक्ष – 4000 रूपये से बढ़ाकर 6000 रूपये मासिक
- जनपद पंचायत सदस्य – 1500 रूपये से बढ़ाकर 5000 रूपयें मासिक

➢ **शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में भी आगामी वर्ष से वृद्धि की जायेगी।**

➢ **डिस्ट्रिक स्ट्राइक फोर्स**

- बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों को वेतन भत्तों तथा पदोन्नति का लाभ देने के लिये ''डिस्ट्रिक स्ट्राइक फोर्स'' नाम से नवीन कैडर का गठन किया जायेगा।

➢ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ किया जायेगा।

➢ आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30 पतिशत कम किया जायेगा।

➢ जनता की मांग के अनुरूप स्थानीय विकास कार्यो की त्वरित स्वीकृति दिये जाने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किया जायेगा।

मुख्य आकर्षण (1/3)

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

(6,000 करोड़)

वार्षिक सहायता 10,000 रूपये प्रति एकड़

अंतिम 02 वर्षो में 10,152 करोड़ रूपये किसानों को भुगतान

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

भूमिहीन कृषि मजदूरों को वार्षिक सहायता की राशि को 6 हजार रूपये से बढ़ाकर 7 हजार रूपयें

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(1702 करोड़)

5 एच.पी. कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय

(₹2600 करोड़)

4 लाख 80 हजार कृषकों को कृषि पंपों के संचालन हेतु रियायती दर पर बिजली

सिंचाई हेतु 300 करोड़ के नवीन कार्य

- कुल 1705 नवीन कार्यो का प्रावधान बजट में किया गया है जिससे 2 लाख 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
- विगत 3 वर्ष के अल्पकाल में वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल 10 लाख 90 हजार से बढ़कर 13 लाख हेक्टेयर हो चुका है।

उत्पादों की बिक्री

- 30 संजीवनी केन्द्र से ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' ब्राण्ड के उत्पादों का विक्रय
- प्रत्येक नगरीय निकाय में सी–मार्ट की स्थापना की जायेगी, जहां स्व–सहायता समूह के उत्पादों का विक्रय किया जायेगा– 5 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री रेशम मिशन

- रैली ककून का क्रय करने हेतु ग्राम नानगूर विकासखण्ड जगदलपुर में ककून बैंक की स्थापना।
- संग्रहित रैली ककून 200 स्व–सहायता समूहों को धागाकरण के लिए वितरण।
- 200 स्व–सहायता समूहों के लगभग 4000 महिलाओं को प्रतिमाह 6 से 7 हजार तक की अतिरिक्त आय।

मुख्य आकर्षण (2/3)

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय

- 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 1 लाख 35 हजार विद्यार्थियों का प्रवेश
- स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय भी प्रारंभ किये जायेंगे

छात्रावास भवन

- 106 नवीन छात्रावास आश्रम के लिये 50 करोड़ का प्रावधान;
- मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्रावास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान;
- विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में स्नातक छात्रावास हेतु 1 करोड़ का प्रावधान।

उच्च शिक्षा

- 16 स्नातक एवं 23 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में नवीन संकाय
- 18 शासकीय महाविद्यालयों के लिए नवीन भवन, 22 शासकीय महाविद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापन कक्षों का निर्माण
- शासकीय महाविद्यालय, सीतापुर में ऑडिटोरियम का निर्माण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

- हायर सेकेण्डी स्कूल के विद्यार्थियों के मांग अनुसार 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नवीन ट्रेड प्रारंभ
- वर्ष 2022–23 में 10 करोड़ 96 लाख का प्रावधान

राष्टीय स्वास्थ्य मिशन (1200 करोड़)

स्वास्थ्य अधोसंरचना

प्रधानमंत्री आयुषमान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत 580 करोड़ का प्रावधान

'मोर जमीन मोर मकान' तथा 'मोर मकान मोर चिन्हारी'–शहरी निर्धन परिवारों हेतु (₹450 करोड़)

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना – 50 करोड़

- 14 नगर निगमों में 60 मोबाईल एम्बुलेंस एवं दाई–दीदी क्लीनिक की स्थापना
- योजना का प्रदेश के नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में लागू किया जायेगा

जल जीवन मिशन

- 48 लाख 60 हजार परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन
- 1000 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना – 150 करोड़

शासकीय भवनों जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी इत्यादि को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु

16000 करोड़ के सड़क एवं पुल निर्माणाधीन

खेल

- राजीय गांधी युवा मितान क्लब–75 करोड़
- ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1,605 क्लब का गठन

मुख्य आकर्षण (3/3)

4 नवीन जिले (1100 पद)

एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो, सतर्कता सेल एवं शिकायत सेल (23 नवीन पद)

रायपुर चिकित्सा महाविद्यालय – 150 पद

चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में कार्डियोवेस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों का सृजन

नवीन तहसील एवं नवीन अनुविभाग कार्यालय

- 6 नवीन तहसील – 84 पद
- 11 नवीन अनुविभाग – 77 नवीन पद

- ❑ **बिलासपुर एवं जगदलपुर में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था हेतु – 114 नवीन पद**
- ❑ **3 नवीन पुलिस चौकी – 99 पद**
- ❑ **5 पुलिस चौकियों का उन्नयन – 226 पद**

45 नवीन पदों का सृजन

- **जगरगुण्डा, जिला सुकमा में 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र**
- **अहिवारा, जिला दुर्ग में 10 बिस्तर एन.आर.सी. की स्थापना**

चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों को राहत

- 16 अनियमित वित्तीय कंपनियों से 16 करोड़ 96 लाख की वसूली
- 17 हजार 404 निवेशकों को 11 करोड़ 23 लाख राशि की वापसी

नारायणपुर जिले का अबुझमाड क्षेत्र

- 237 ग्रामों का अभी तक राजस्व सर्वे नहीं किया गया है
- 6 गांवों का सर्वे पूर्ण कर 676 किसानों को अस्थायी भू–अभिलेख उपलब्ध कराया गया

छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था – एक नजर में (1/2)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव) राशि रूपये करोड़ में

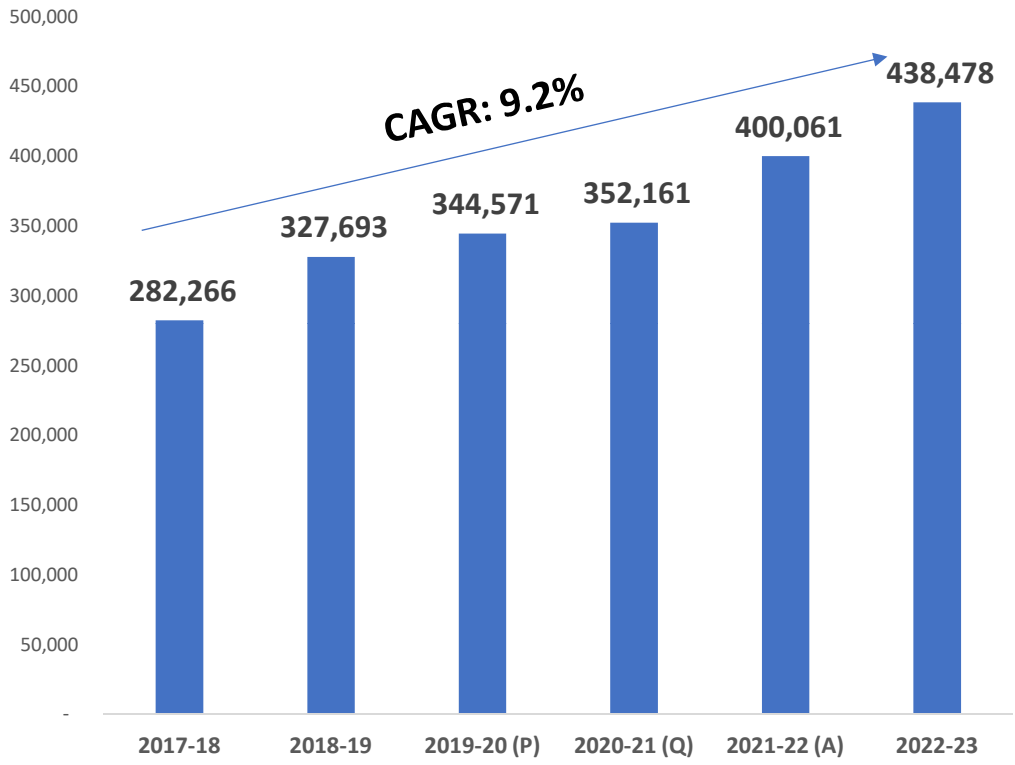

वर्ष 2021–22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का क्षेत्रवार घटक (प्रचलित भाव)

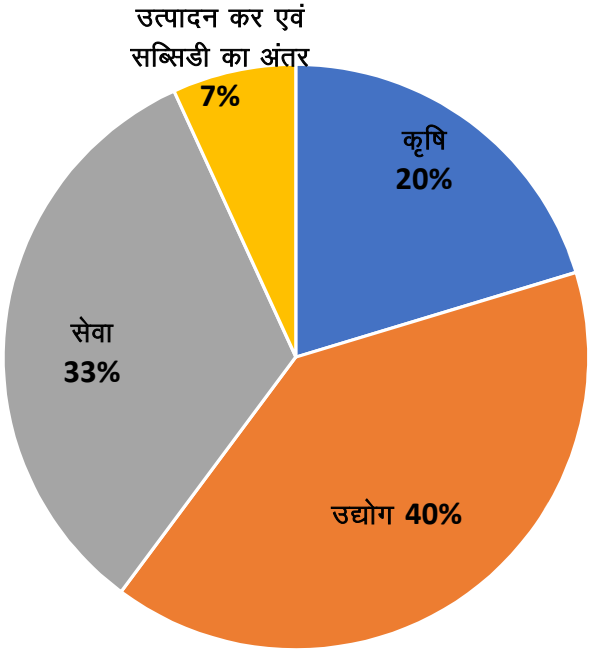

(P)=Provisional Estimates, (Q) =Quick Estimates, (A)=Advance Estimates (State Economic Survey 2021-22)
Average of last 9 year's growth is used to estimate the growth of 2021-22 then moving average is applied afterwards

छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था – एक नजर में (2/2)

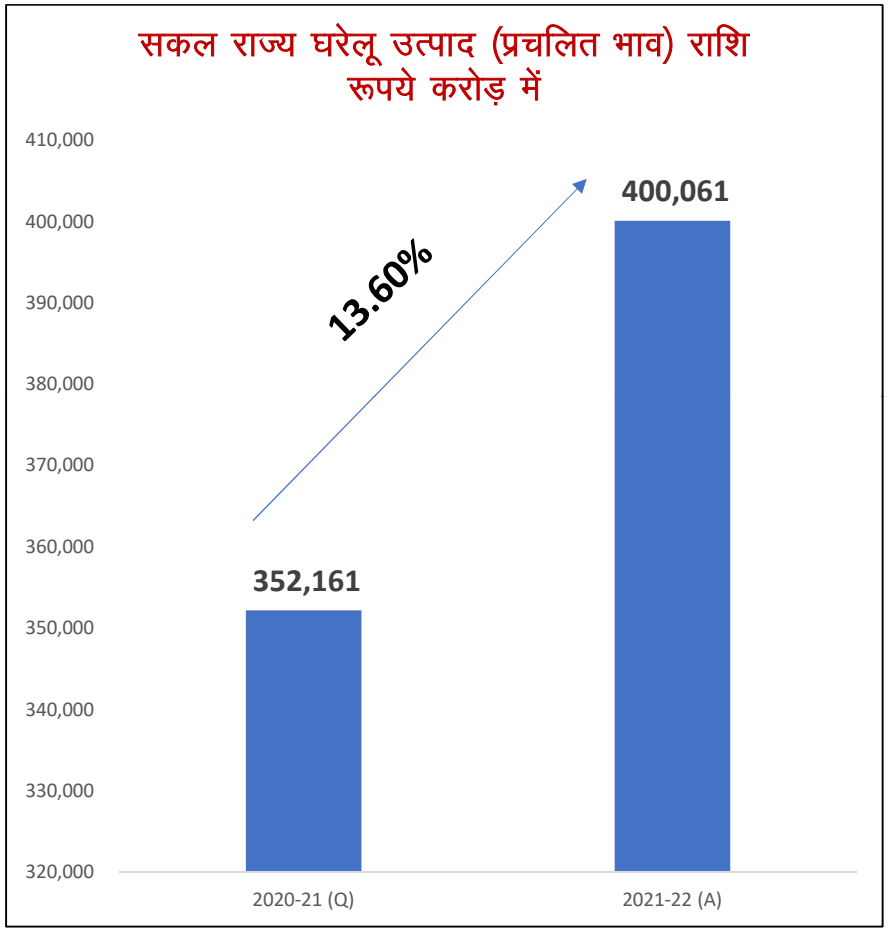

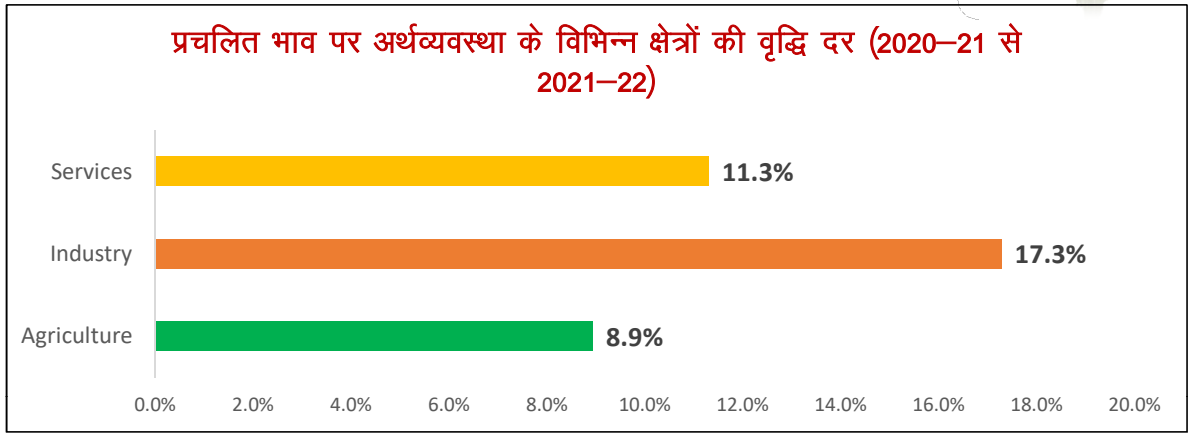

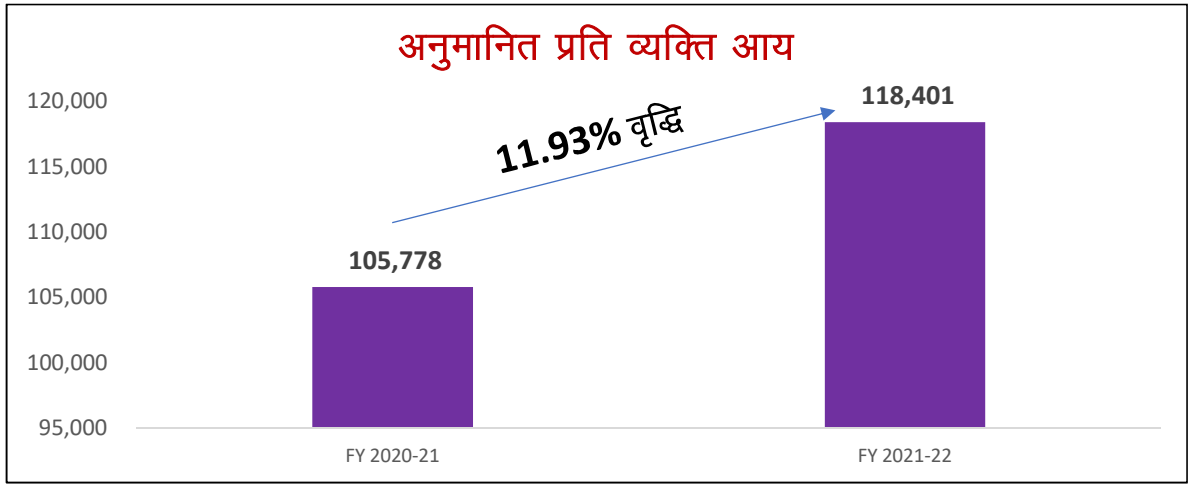

बजट वर्ष 2022–23 – एक नजर में (1/2)

वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमान – ₹ 1,04,000 करोड़

बजट अनुमान एवं व्यय

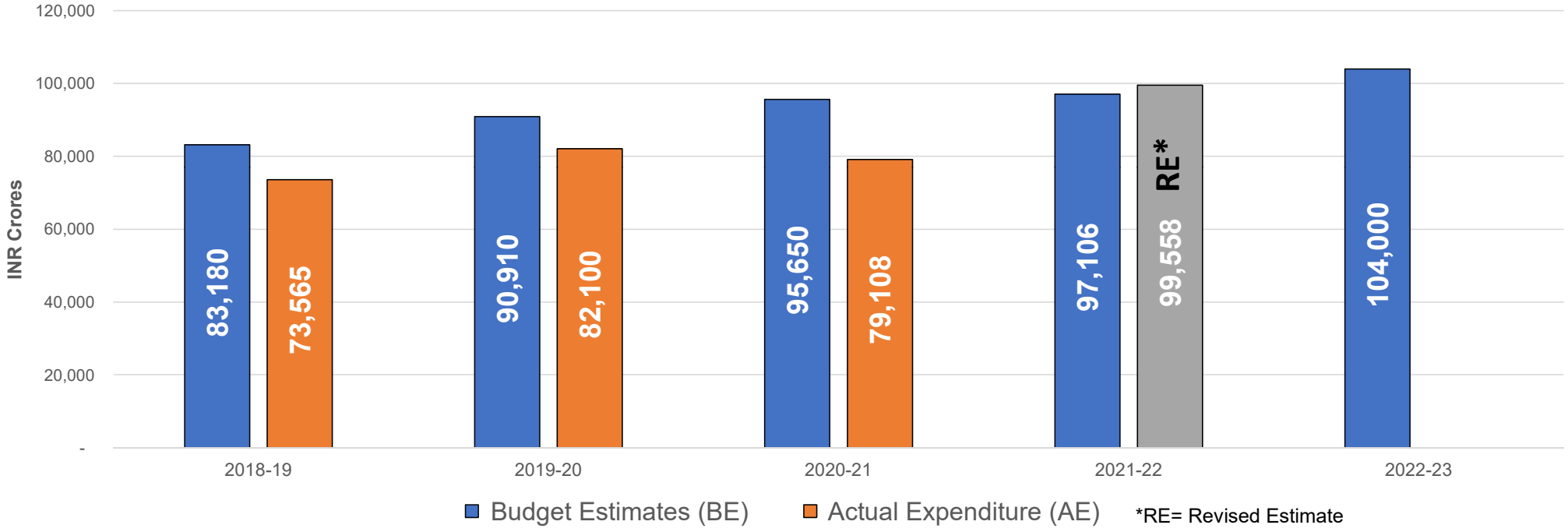

गत वर्ष के बजट अनुमान (2021–22) से बजट अनुमान (2022–23) में 7 प्रतिशत की वृद्धि

बजट वर्ष 2022–23 – एक नजर में (2/2)

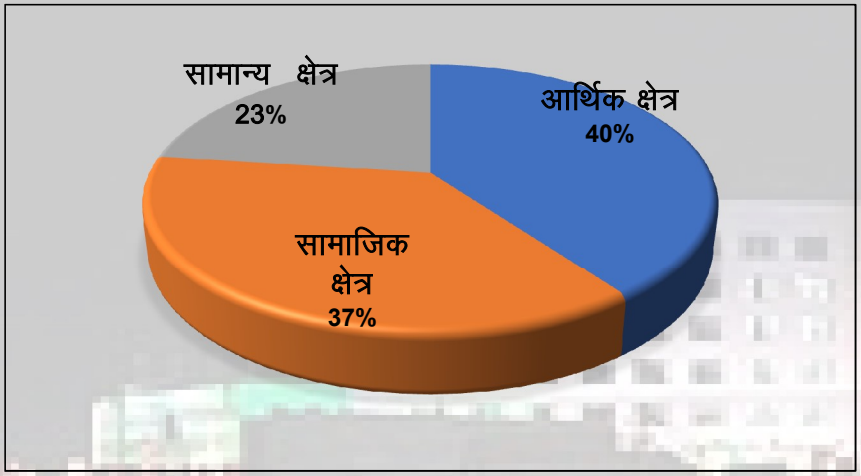

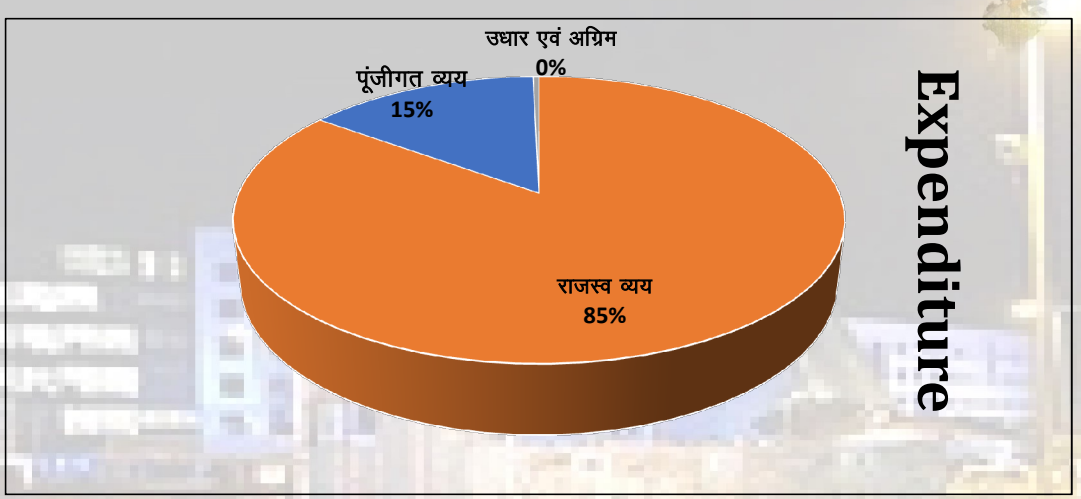

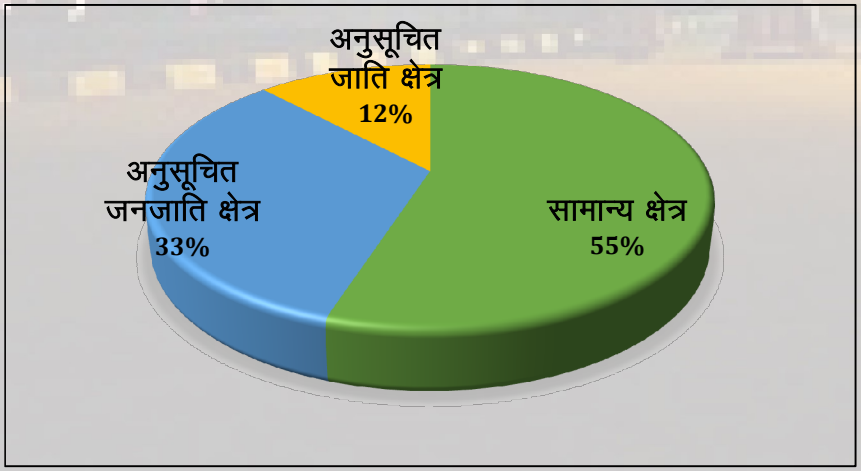

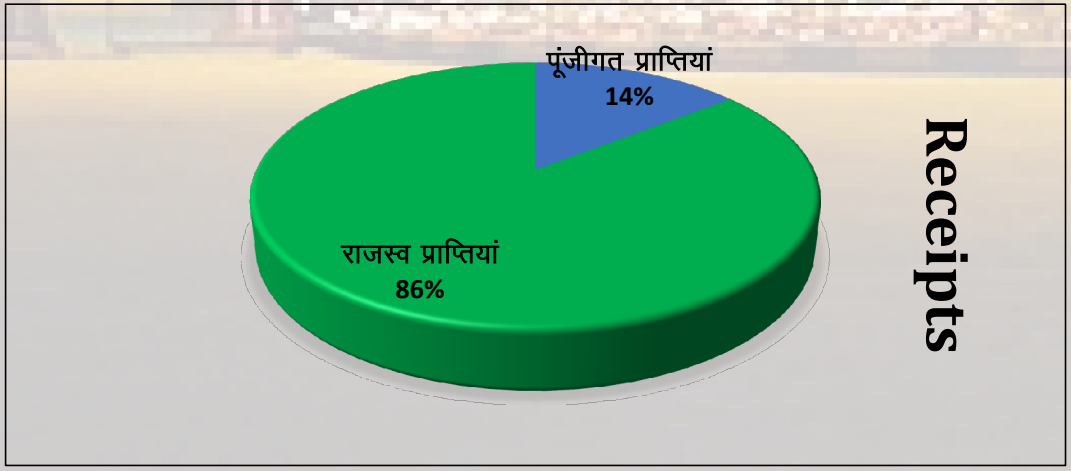

बजट वर्ष 2022–23 – व्यय एक नजर में

All values in INR Crores

वर्ष 2022–23 में विभागवार बजट प्रावधान (मुख्य 10 विभाग)

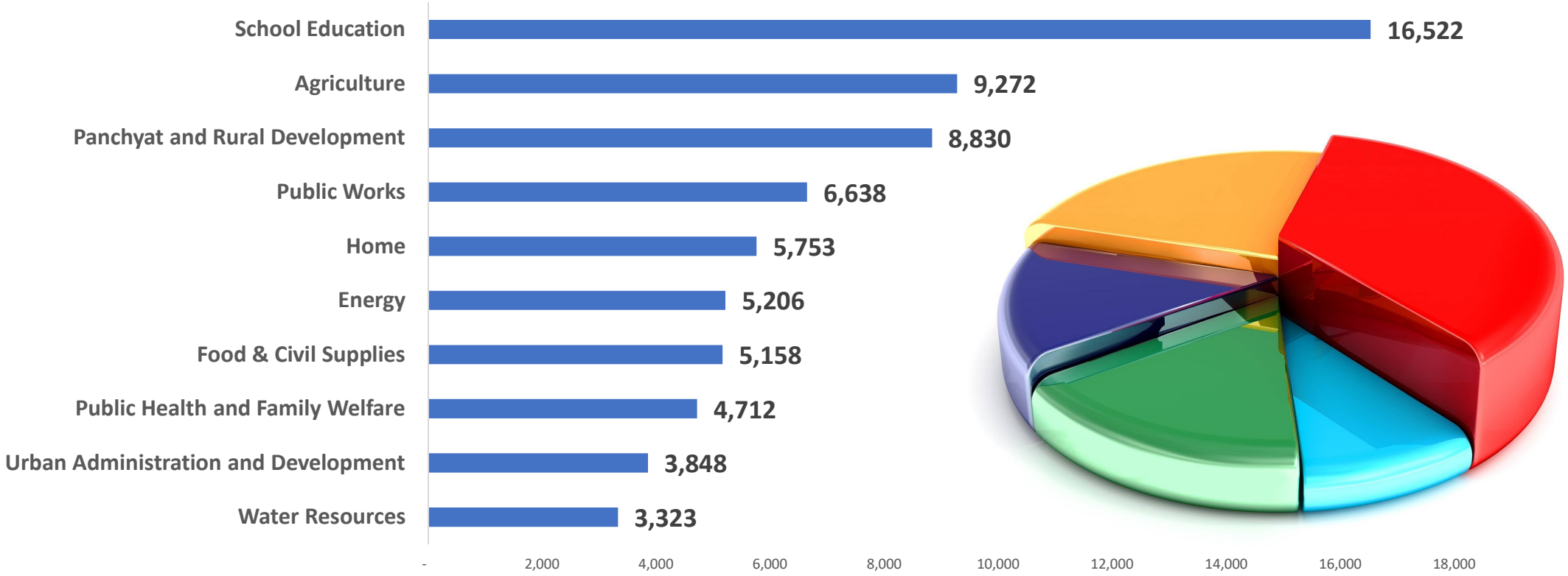

Note – Finance Department, whose budget largely comprises of debt servicing obligations (principal & interest payment) and pension payments (OPS and government contribution to NPS), is not included in the above graph.

कृषि

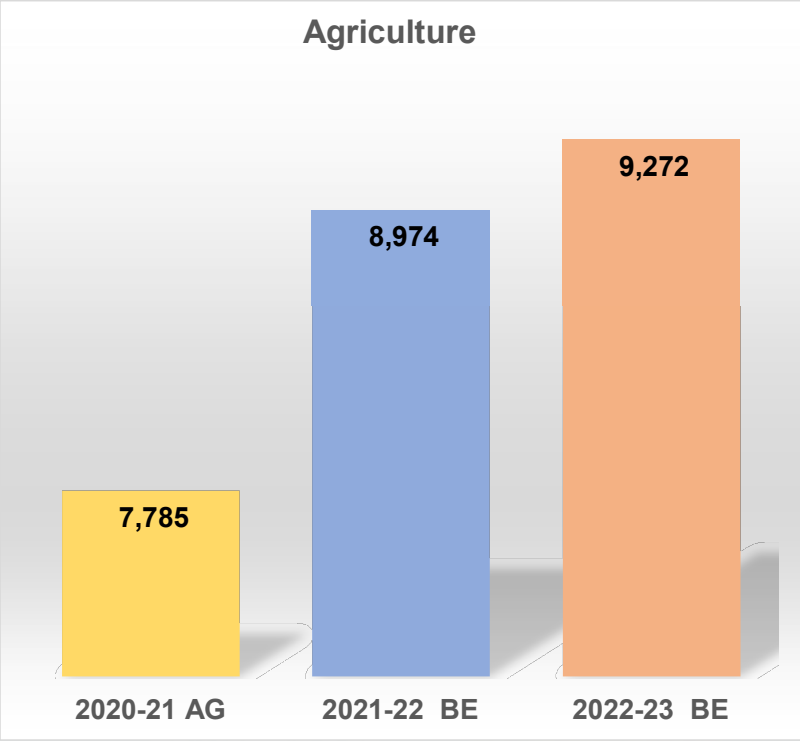

All values in INR Crores

(6,000 करोड)
वार्षिक सहायता राशि 10 हजार प्रति एकड
गत 2 वर्षो में 10 हजार 152 करोड़ का किसानों को भुगतान

महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्क (600 करोड़)

फसल बीमा योजना (575 करोड़)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (323 करोड)

चिराग योजना (200 करोड़)

(200 करोड)
भूमिहीन कृषि मजदूरों को वार्षिक सहायकता की राशि 6000 से 7000 प्रतिवर्ष

- 17.99 लाख किसानों के 8230 करोड़ रूपयें की ऋण माफी
- धान खरीदी 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से
- खरीफ फसल वर्ष 2018–19 की खरीदी पर 6022 करोड़ बोनस

सिंचाई सुविधा

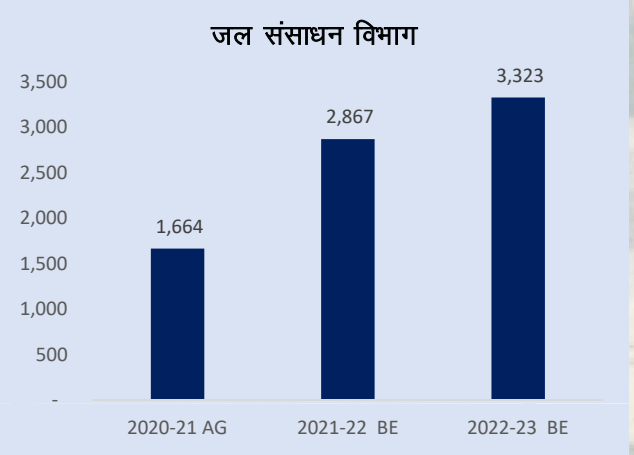

All values in INR Crores

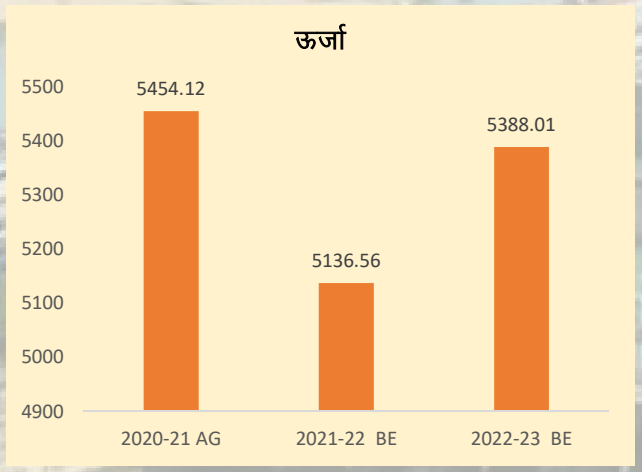

All values in INR Crores

विगत 3 वर्ष के अल्पकाल में वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल 10 लाख 90 हजार से बढ़कर 13 लाख हेक्टेयर

नवीन कार्य (300 करोड़)

- कुल 1705 नवीन कार्यो का प्रावधान बजट में किया गया है जिससे 2 लाख 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित

सौर सुजला योजना

(₹416.90 करोड़)

3 एचपी एवं 5 एचपी के 15000 अतिरिक्त सिंचाई पंपों की स्थापना

प्रधानमंत्री कुसुम योजना

(100 करोड़)

10000 सोलर पंपों का स्थापना

5 एच.पी. कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय

(₹2600 करोड़)

4 लाख 80 हजार कृषकों को कृषि पंपों के संचालन हेतु रियायती दर पर बिजली

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

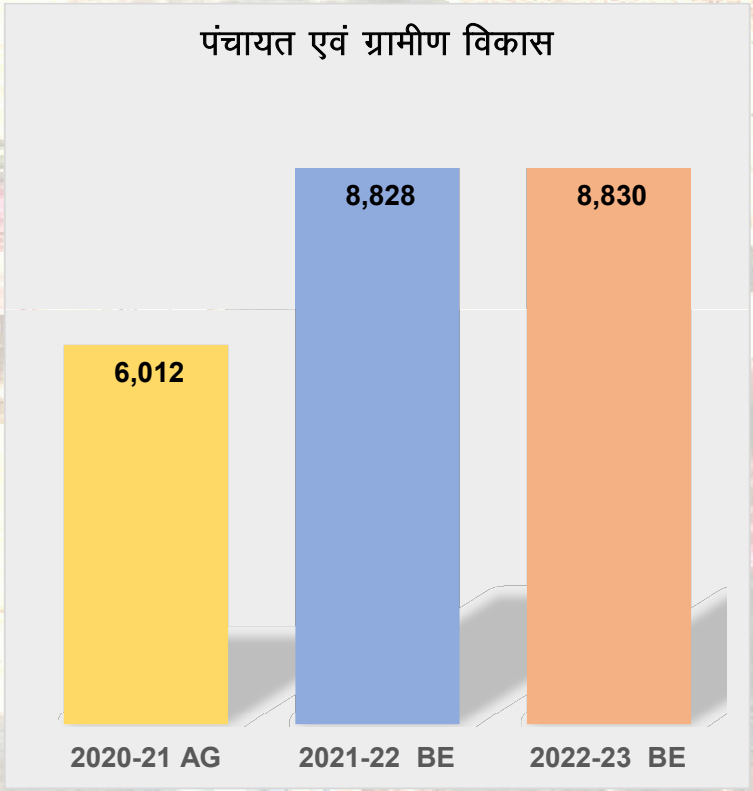

All values in INR Crores

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
(1702 करोड़)

पंचायतों को 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान
(1114 करोड़)

स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण
(500करोड़)

मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना
(200 करोड़)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (1675 करोड़)

- 900 कि.मी. एवं 24 वृहद पुलों का लक्ष्य
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 47 स्टील के पुल

राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन (450 करोड़)

मिलाप योजना के अंतर्गत राजनांदगांव एवं कवर्धा जिलों में 17,315 प्रवासी मजदरों की पहचान कर इनके समग्र विकास के लिये कार्य

ग्राम पंचायत को मूलभूत कार्यो हेतु अनुदान (260 करोड़)

ग्रामीण रोजगार के लिए मुख्य पहल

- नरवा, गरूआ, घुरूआ, बाडी
- गोधन न्याय योजना
- चाय कॉफी बोर्ड की स्थापना
- मछलीपालन एवं लाख उत्पादन को कृषि के समान दर्जा
- मिलेट मिशन और वाणिज्यिक वृक्षारोपण
- स्थानीय उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल्स के नाम से ब्राण्ड निर्माण

शिक्षा

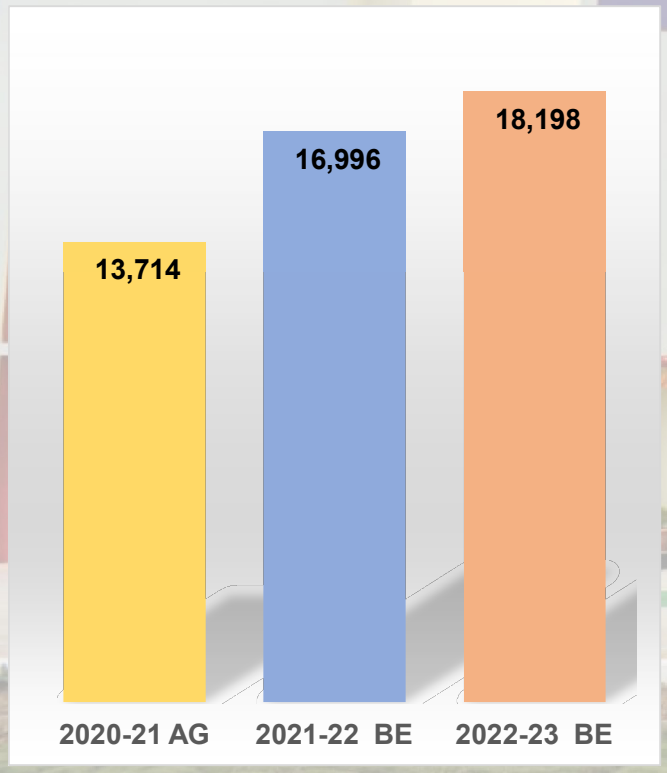

All values in INR Crores

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय

- 171 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 1 लाख 35 हजार छात्रों का प्रवेश;
- स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय भी प्रारंभ किये जायेंगे।

नवीन विद्यालय भवन

- 40 उच्च विद्यालय एवं 17 उच्चतर माध्यामिक विद्यालय;
- 50 करोड़ का प्रावधान।

विद्यालयों का उन्नयन

- 11 माध्यामिक विद्यालयों को उच्च विद्यालय में;
- 12 उच्च विद्यालय का उच्चतर माध्यामिक विद्यालय में।

छात्रावास भवन

- 106 नवीन छात्रावास आश्रम के लिये 50 करोड़ का प्रावधान;
- मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्रावास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान;
- विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में स्नातक छात्रावास हेतु 1 करोड़ का प्रावधान।

उच्च शिक्षा

- 16 स्नातक महाविद्यालयों और 23 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में नवीन संकाय;
- 18 शासकीय महाविद्यालयों के लिए नवीन भवन, 22 शासकीय महाविद्यालयों में अतिरिक्त अध्ययन कक्ष का निर्माण;
- शासकीय महाविद्यालय, सीतापुर में ऑडिटोरियम का निर्माण।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

- हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों की मांग के अनुसार 28 आईटीआई में नवीन ट्रेड प्रारंभ किये जाएंगे;
- वित्त वर्ष 2022–23 में 10.96 करोड़ का प्रावधान।

स्वास्थ्य

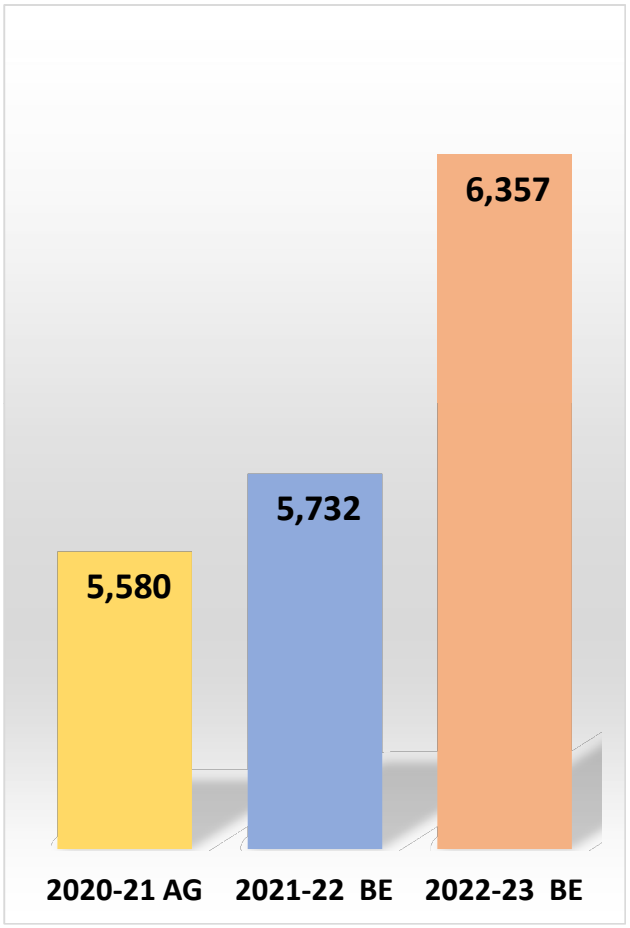

All values in INR Crores

550 करोड़

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
1200 करोड़

हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 580 करोड़ का प्रावधान

रायपुर मेडिकल कॉलेज में 150 पद
रायपुर मेडिकल कॉलेज में हृदय एवं थोरैसिक सर्जरी विभाग में 150 पद स्वीकृत।

अस्पताओं के गुणवत्ता प्रमाणन
3 जिला अस्पताल और 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित 27 अस्पतालों का प्रमाणन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत किया गया है।

विगत 2 वर्षों में नवीन नियुक्तियां
- 1329 चिकित्सा अधिकारी;
- 282 बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता;
- 328 बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता;
- 278 लैब तकनीशियन;
- 192 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

45 नवीन पद सृजन
- जगरगुंडा (सुकमा जिला) – 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
- अहिवारा (जिला दुर्ग) – 10 बिस्तरों वाला एनआरसी प्रतिष्ठान

खैरागढ़ में 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल
अस्पताल भवन निर्माण के लिए बजट प्रावधान

महिला एवं बाल विकास

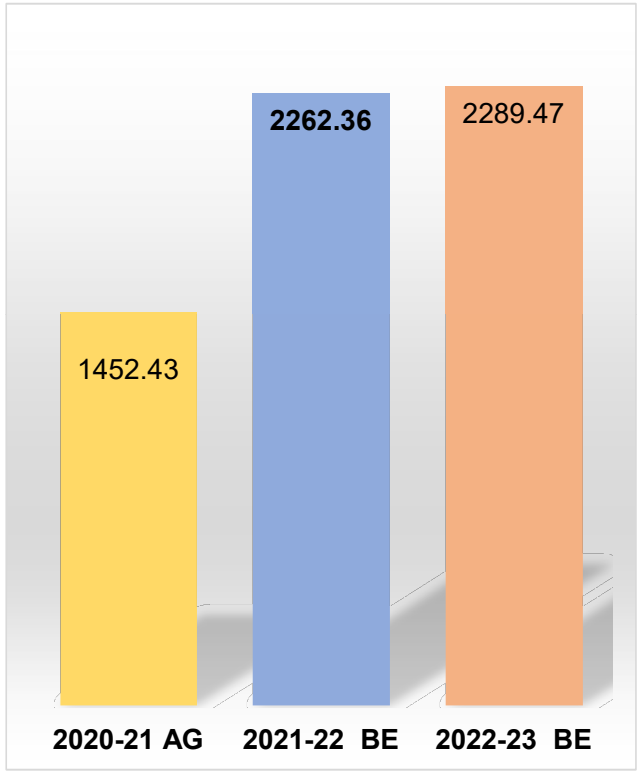

All values in INR Crores

2019 में चिन्हांकित 4.33 लाख बच्चों में से 1.72 लाख बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं

छत्तीसगढ़ महिला कोष

- महिला स्व–सहायता समूह को रूपये 12.77 करोड़ रुपये की कर्जमाफी;
- पहले ऋण की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख की गई;
- प्रथम ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर 2 से 4 लाख तक के द्वितीय ऋण का प्रावधान किया गया है;
- 5.2 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जो वित्त वर्ष 2018–19 के प्रावधान से 30 प्रतिशत अधिक है।

छत्तीसगढ़ में बाल कुपोषण 31.3 प्रतिशत है जो भारत के औसत 32.1 प्रतिशत से कम है।

एकीकृत बाल विकास योजना, मुख्यमंत्री बाल सन्दर्भ योजना, वजन उत्सव, नव जतन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पोषण अभियान के कारण पिछले 3 वर्षों में कुपोषण 8.7 प्रतिशत कम हुआ

नगरीय विकास

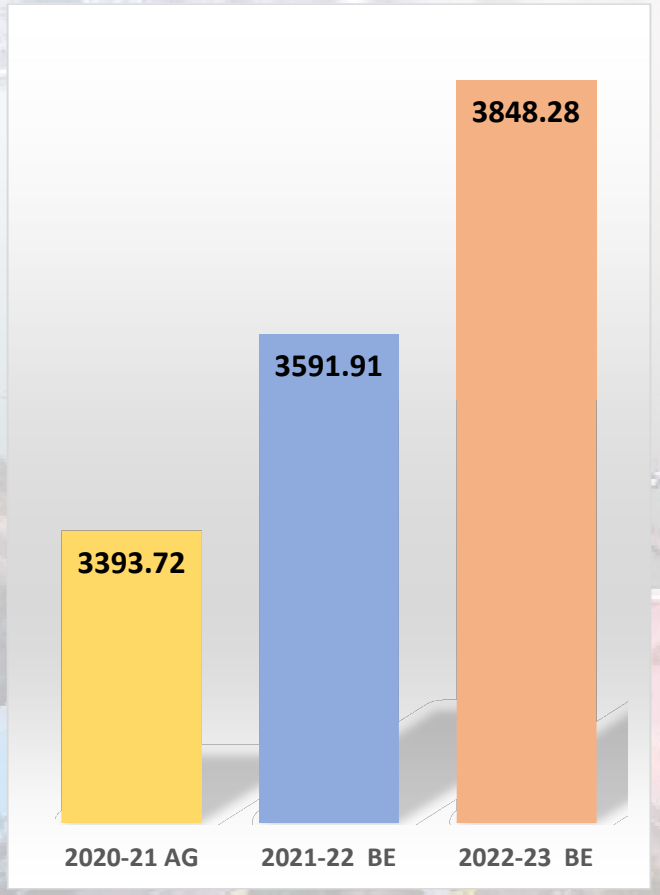

All values in INR Crores

जल आवर्धन योजना
380 करोड़

'मोर जमीन मोर मकान' तथा 'मोर मकान मोर चिन्हारी'–शहरी निर्धन परिवारों हेतु (₹450 करोड़)

मिशन अमृत 2.0
(₹200 करोड़)
स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल
हर घर में नल जल कनेक्शन

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना – 50 करोड़

- 14 नगर निगमों में 60 मोबाईल एम्बुलेंस एवं दाई–दीदी क्लीनिक की स्थापना
- योजना का प्रदेश के नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में लागू किया जायेगा

कोरबा, दंतेवाड़ा, सक्ती, शिवनगर, चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (20 करोड़)

शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए, संपत्ति कर की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर दिशानिर्देश दर की तुलना में 30 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।

वन

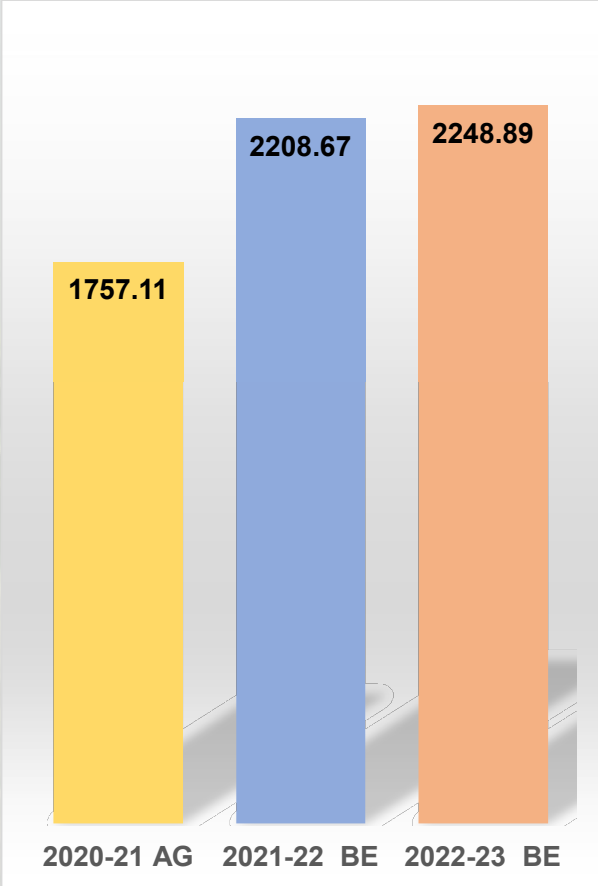

All values in INR Crores

कैम्पा मद के अंतर्गत विविध कार्यों के लिये 300 करोड़ का प्रावधान

- वनों में भू–जल संरक्षण;
- वन संरक्षण;
- वन प्राणियों के रहवास में सुधार;
- 1950 नालों को उपचारित करना।

उत्पादों की बिक्री

- 30 संजीवनी केन्द्र से ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' ब्राण्ड के उत्पादों का विक्रय
- प्रत्येक नगरीय निकाय में सी–मार्ट की स्थापना की जायेगी, जहां स्व–सहायता समूह के उत्पादों का विक्रय किया जायेगा– 5 करोड़ का प्रावधान

राष्ट्रीय स्तर पर कार्य की पहचान

- भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत 4 पुरस्कार
- वन धन योजना के तहत प्रसंस्करण के लिए 4 पुरस्कार
- नवीनता और नवाचार के लिए 3 पुरस्कार

लघु वनोपज संघ

- 65 वनोपजों का क्रय किया जा रहा है;
- वित्त वर्ष 2020–21 में 153 करोड़ रुपये की वनोपज क्रय की गई, जो 2018 में 3. 81 करोड़ रुपये के क्रय से अधिक है।

लोक निर्माण विभाग

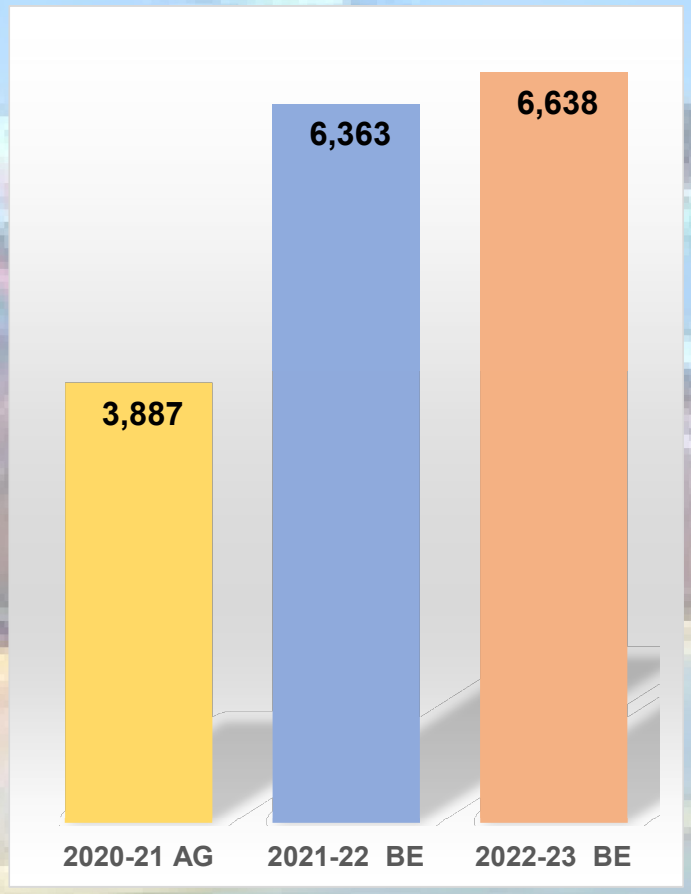

All values in INR Crores

16000 करोड़ के सड़क एवं पुल निर्माणाधीन हैं।

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना (150 करोड़)

- शासकीय भवनों, जैसे– विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी आदि तक पक्की सड़क का निर्माण।

659 नवीन कार्य

- सड़क कार्य– 365 करोड़
- वृहद एवं मध्यम पुल– 103 करोड़
- 8 नवीन शासकीय विश्राम गृह का निर्माण– 3 करोड़
- 15 रेल्वे ओव्हर ब्रिज सर्वे– 8.65 करोड़

मुख्य आबंटन

- राज्य राजमार्ग– 228 करोड़;
- मुख्य जिला मार्ग– 458 करोड़;
- ग्रामीण मार्ग– 810 करोड़;
- वृहद एवं मध्यम पुल– 315 करोड़
- रेल्वे ओव्हर ब्रिज– 90 करोड़

राजस्व एवं पुलिस प्रशासन

4 नवीन जिले– 1100 पद

छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति एवं पुलिस मेमोरियल टावर

एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो, सतर्कता सेल एवं शिकायत सेल– 23 पद

अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये ब्लॉक मुख्यालयों में आवासीय भवन– 58 करोड़

रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में हाई–टेक अपराधों की जांच हेतु एन्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट की स्थापना

पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन, नवा रायपुर में पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये 320 निर्मित भवनों का क्रय– 65 करोड़

डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स कैडर

- बस्तर संभाग के सहायक आरक्षकों को वेतन–भत्ते एवं पदोन्नति की सुविधा प्रदान करने हेतु

नवीन तहसील एवं अनुविभाग

- 6 नवीन तहसील (84 पद)
- 11 नवीन अनुविभाग (77 पद)

- एयरपोर्ट सुरक्षा– बिलासपुर एवं जगदलपुर– 114 पद
- 3 नवीन पुलिस चौकी– 99 पद
- 5 चौकियों का उन्नयन– 226 पद

सुशासन

जन प्रतिनिधित्व

- जनता की मांग के अनुरूप स्थानीय विकास के कार्यों को त्वरित स्वीकृति दिये जाने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ की गई;
- ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णय लेने की स्वायत्तता बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षेत्रों के विकास कार्यों के संबंध में इन प्रतिनिधियों धनराशि उपलब्ध कराई गई;
- जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि।

चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों को राहत

- 16 अनियमित वित्तीय कंपनियों से 16 करोड़ 96 लाख की वसूली
- 17 हजार 404 निवेशकों को 11 करोड़ 23 लाख राशि की वापसी

नारायणपुर जिले का अबुझमाड क्षेत्र

- 237 ग्रामों का अभी तक राजस्व सर्वे नहीं किया गया है
- 6 गांवों का सर्वे पूर्ण कर 676 किसानों को अस्थायी भू–अभिलेख उपलब्ध कराया गया

अन्य मुख्य क्षेत्र

जल जीवन मिशन

- 48.60 लाख परिवारों को नल जल कनेक्शन
- 1,000 करोड़ का प्रावधान

खेल

- राजीव युवा मितान क्लब (75 करोड़)– ग्रामीण क्षेत्रों में 11,664 एवं शहरी क्षेत्रों में 1,605 क्लब की स्थापना;
- नारायणपुर जिले में मल्ल–खम्भ दक्षता के विकास के लिये मल्ल–खम्भ अकादमी की स्थापना

मुख्यमंत्री रेशम मिशन

- रैली ककून का क्रय करने हेतु ग्राम नानगूर विकासखण्ड जगदलपुर में ककून बैंक की स्थापना।
- संग्रहित रैली ककून 200 स्व–सहायता समूहों को धागाकरण के लिए वितरण।
- 200 स्व–सहायता समूहों के लगभग 4000 महिलाओं को प्रतिमाह 6 से 7 हजार तक की अतिरिक्त आय।

राजस्व एवं वित्तीय घाटा

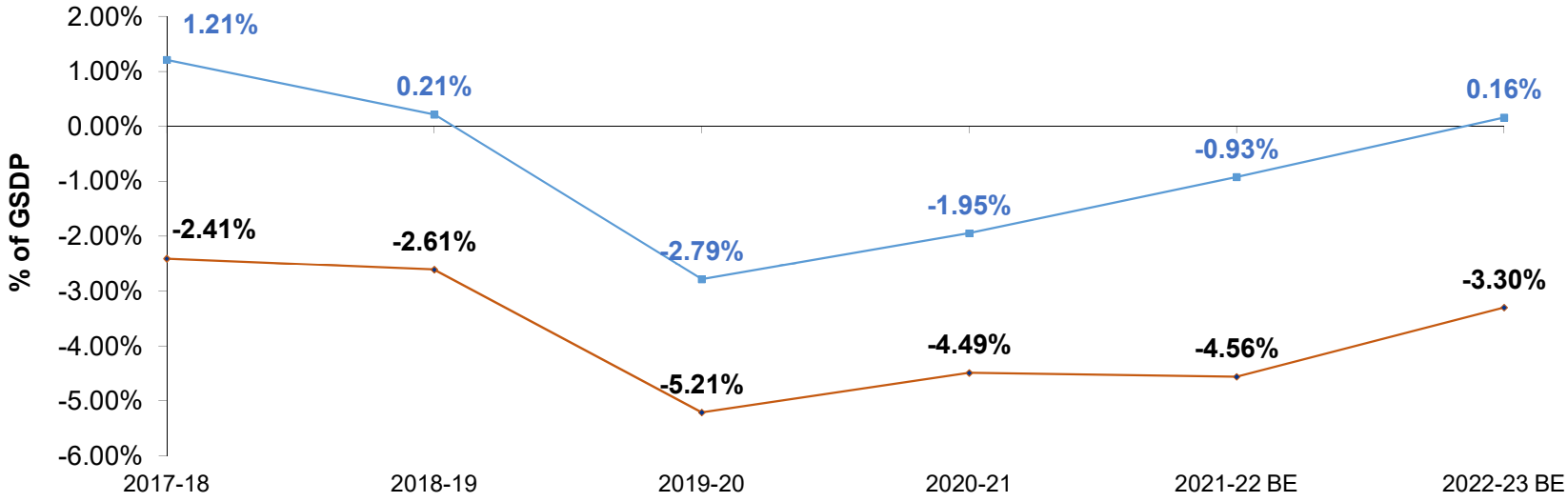

Note - Fiscal deficit of -3.3% takes into account 50 year interest free loan of INR 3400 crores for provided by Government of India under the scheme, 'Scheme of Financial Assistance to States for Capital Expenditure' . If this is not taken into account, fiscal deficit in FY 2022-23 would drop to -2.55%.

बजट वित्तीय वर्ष 2022–23– प्राप्तियां एक नजर में (1/4)

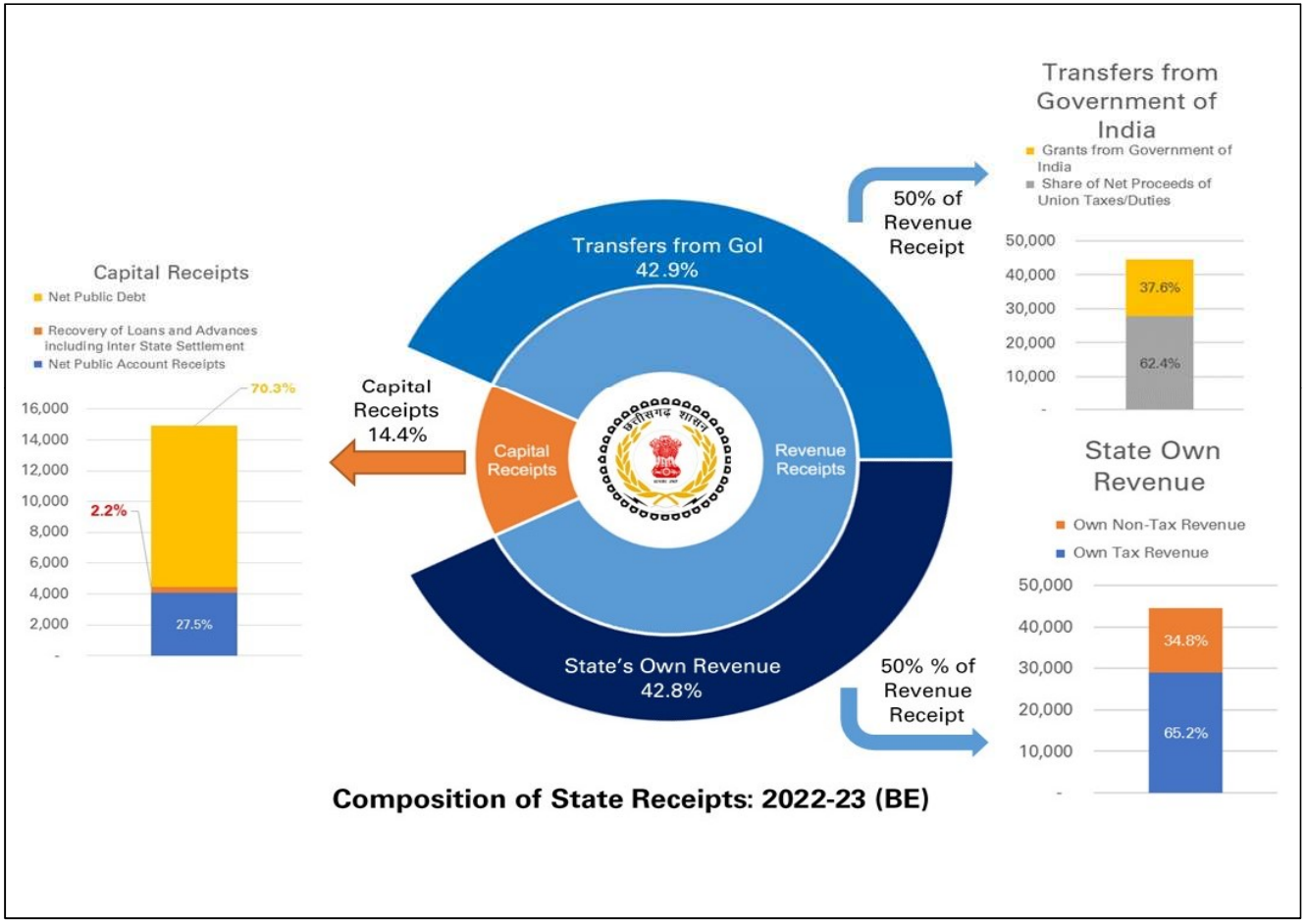

Composition of State Receipts: 2022-23 (BE)

घटक	रूपये करोड़ में	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
राजस्व प्राप्तियां	89,073	85.65%
राज्य का स्वयं का राजस्व	44,500	42.8%
केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	27,823	26.8%
भारत सरकार से अन्य प्राप्तियां	16,750	16.1%
पूंजीगत प्राप्तियां	14,927	14.35%
शुद्ध लोक ऋण	10,500	10.1%
लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियां	4,100	3.9%
उधार एवं अग्रिम की वसूली	327	0.3%
कुल प्राप्तियां	1,04,000	

बजट वित्तीय वर्ष 2022–23– प्राप्तियां एक नजर में (2/4)

राजस्व प्राप्तियां

राज्य का राजस्वः 44,500 करोड़

भारत सरकार से प्राप्तियांः 44,573 करोड़

पूंजीगत प्राप्तियांः 14,927 करोड़

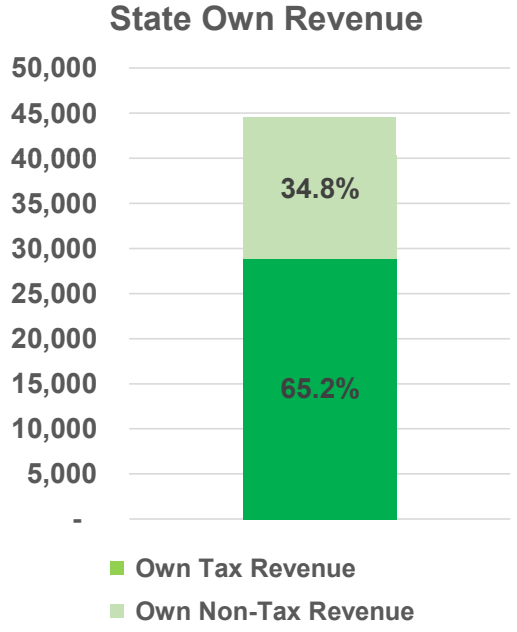

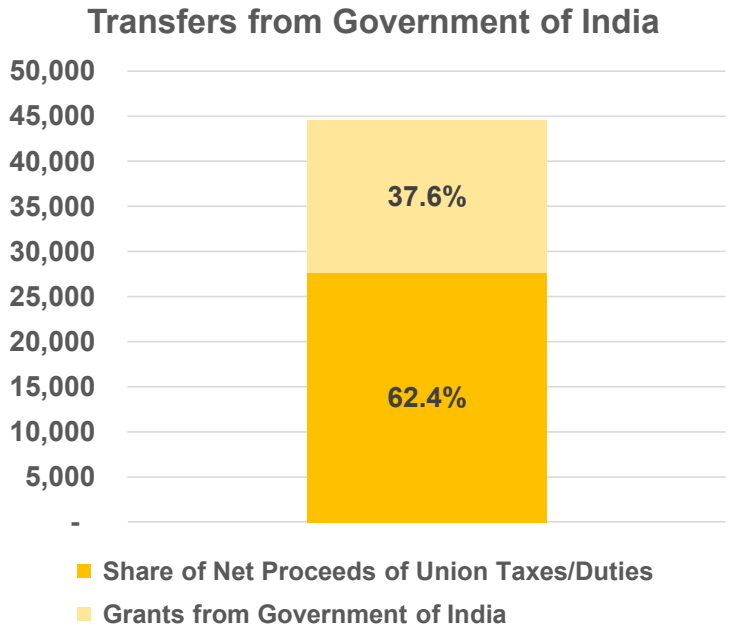

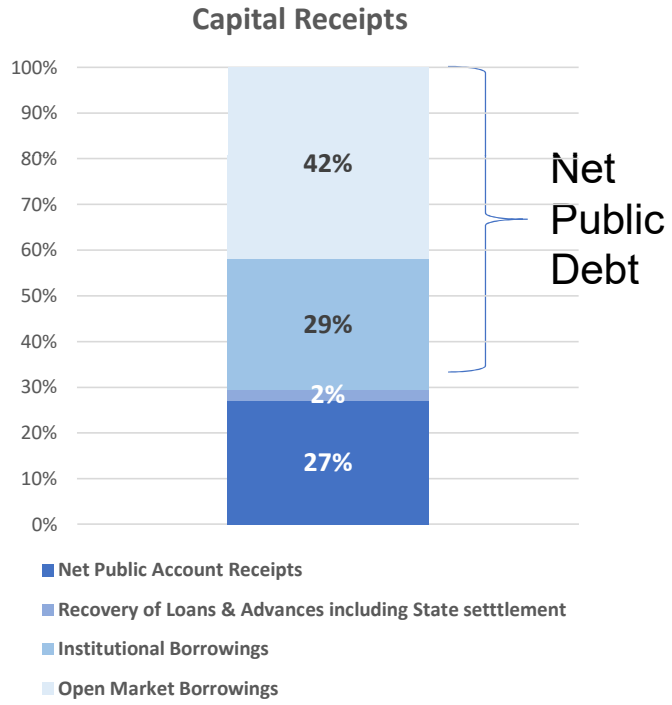

बजट वित्तीय वर्ष 2022–23– प्राप्तियां एक नजर में (3/4)

कुल प्राप्तियां

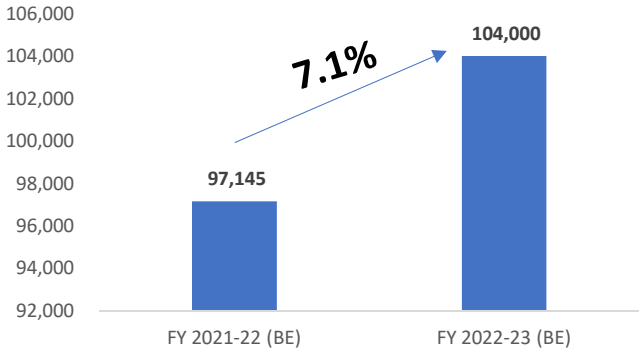

राज्य का राजस्व

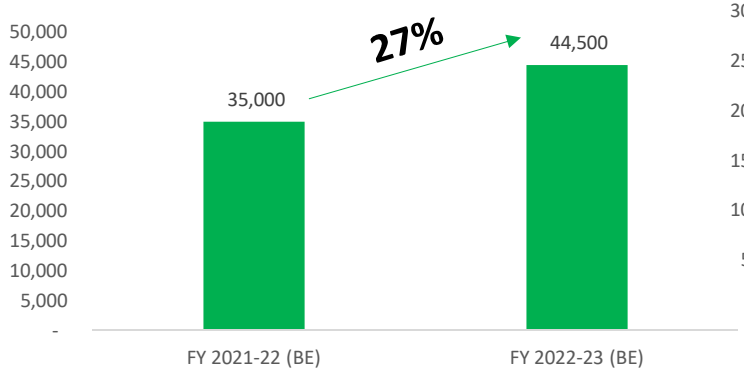

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा

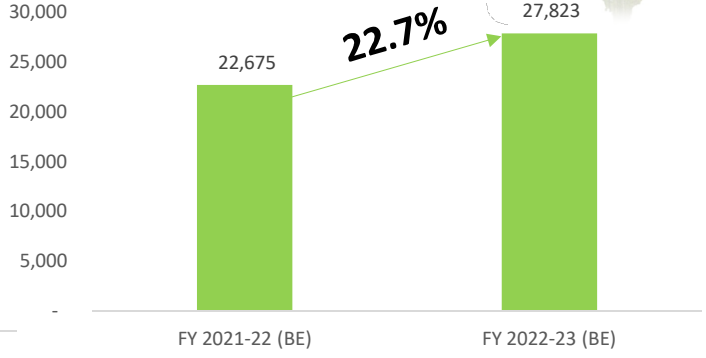

भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान

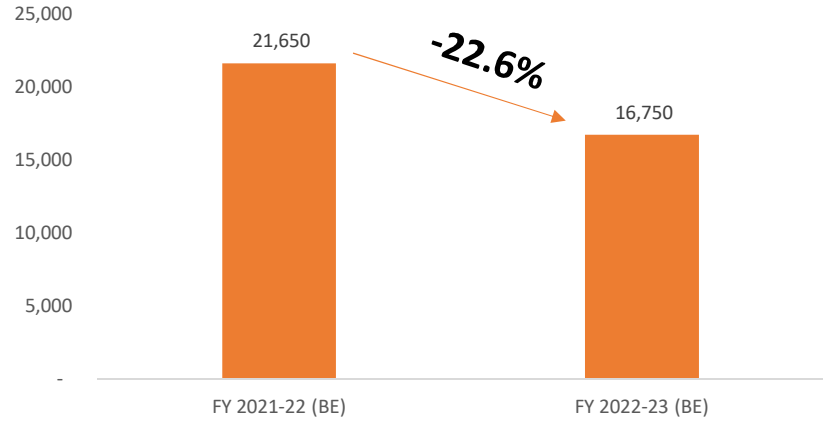

पूंजीगत प्राप्तियां

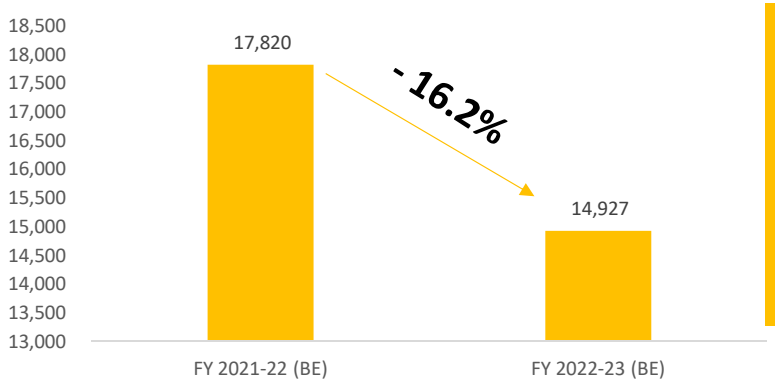

पूंजीगत प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से शुद्ध लोक ऋण प्राप्तियों में रूपये 13,400.01 करोड़ (वित्त वर्ष 2020–21 में) से रूपये 10,500 करोड़ तक की कमी के कारण है। छत्तीसगढ़ शासन ने वित्त वर्ष 2022–23 में अपनी ऋण भार कम करने की योजना बनाई है और व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों पर अधिक निर्भर है।

All values in INR Crores

बजट वित्तीय वर्ष 2022–23– प्राप्तियां एक नजर में (4/4)

राज्य का राजस्व– घटक

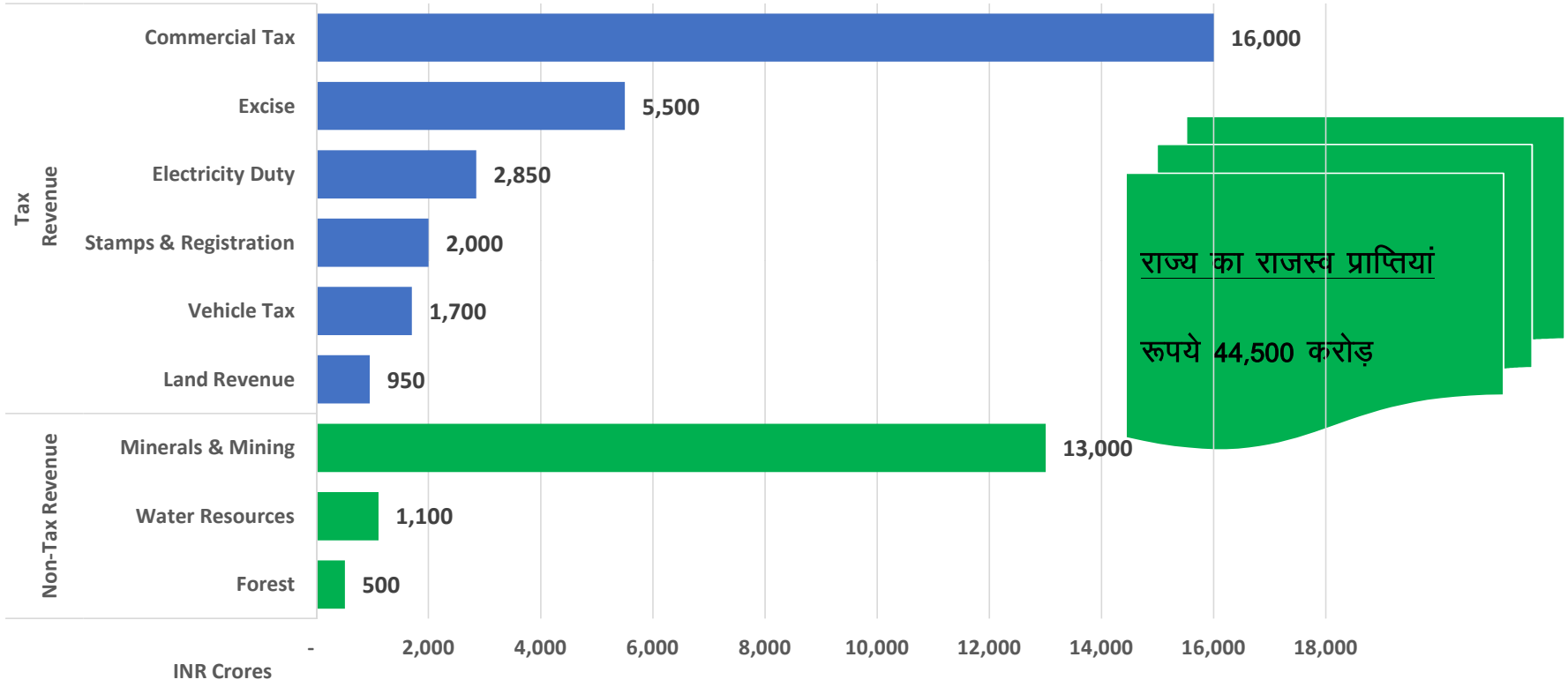

रूपये का जाना

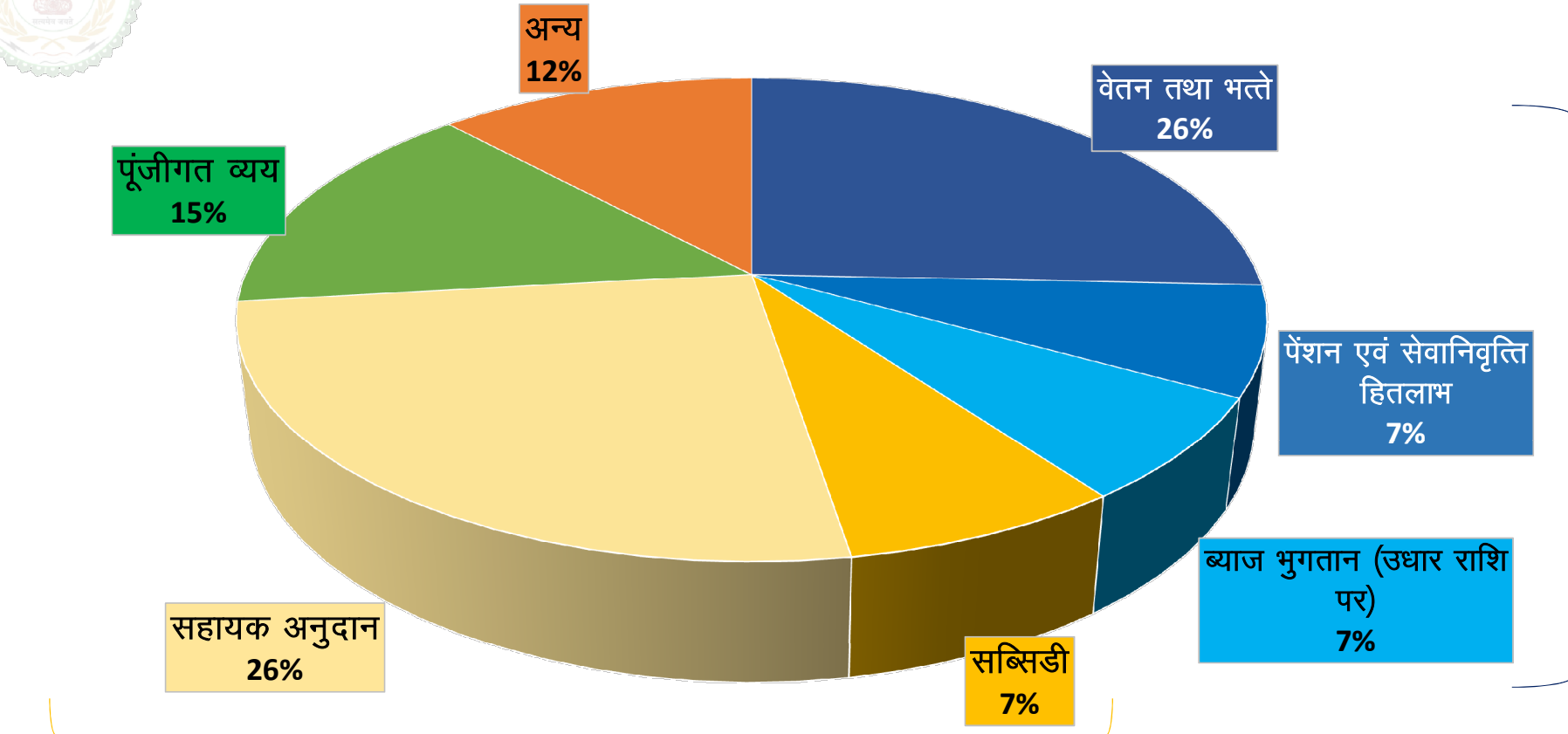

प्रतिबद्ध व्यय (40%)

सहायक अनुदान एवं सब्सिडी (33%)

Grant-in-Aid includes grants given by State Government to Urban Local Bodies, Rural Local Bodies, Government Institutions, Public Corporations and other parastatals of the State Government. Subsidies includes subsidies given by State Government on product/services to different set of beneficiaries

रूपये का आना

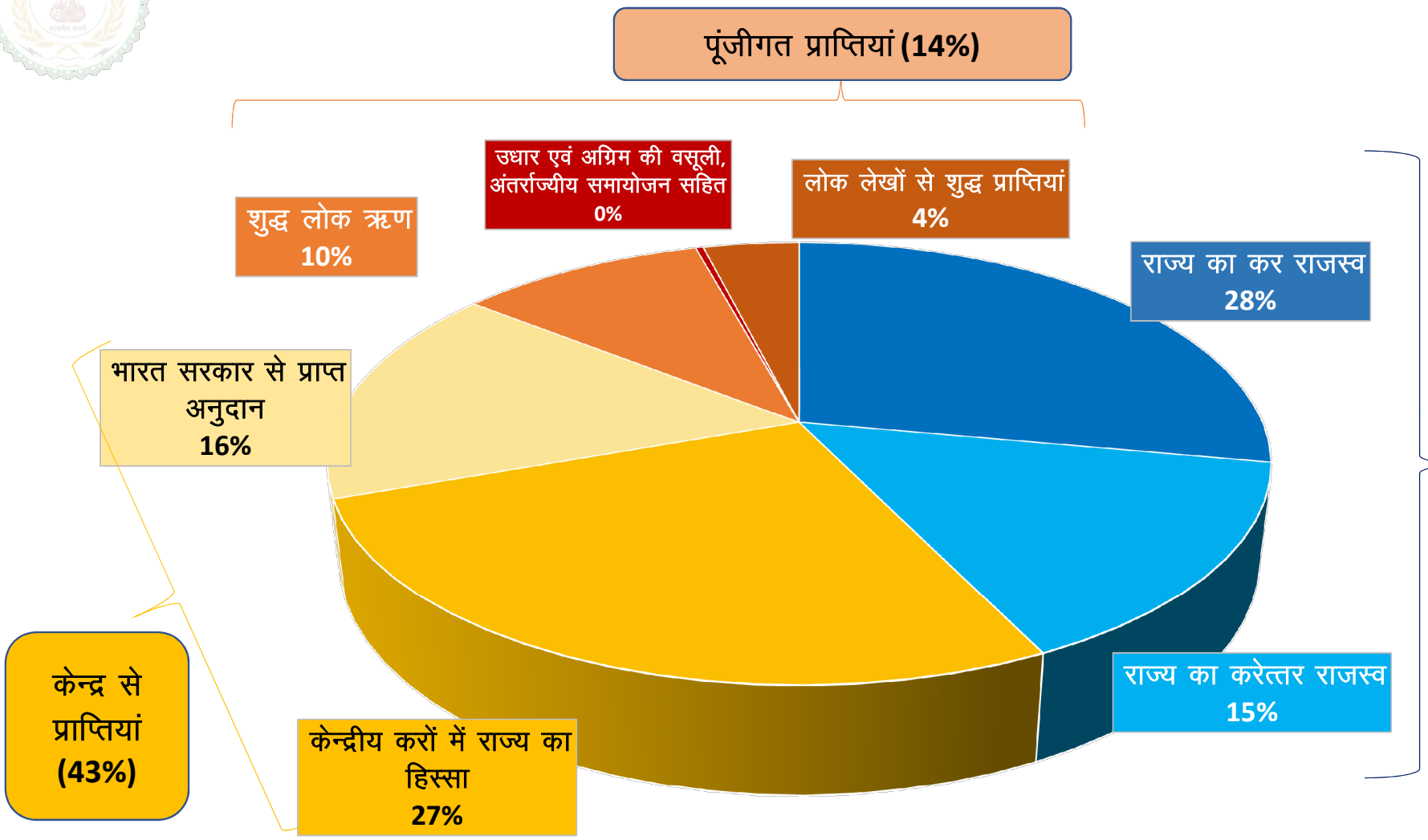
पूंजीगत प्राप्तियां (14%)
उधार एवं अग्रिम की वसूली, अंतर्राज्यीय समायोजन सहित 0%
लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियां 4%
शुद्ध लोक ऋण 10%
राज्य का कर राजस्व 28%
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान 16%
राज्य का राजस्व (43%)
केन्द्र से प्राप्तियां (43%)
राज्य का करेत्तर राजस्व 15%
केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 27%

धन्यवाद

छत्तीसगढ़ शासन

अधिक जानकारी के लिये वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाईट
https://finance.cg.gov.in का अवलोकन करें।